

वश्वास-आधारति वनियिमन

प्रलिमिस के लयि:

[जन वश्वास \(प्रावधानों में संशोधन\) अधनियिम, 2023](#), [पर्यावरण संरक्षण अधनियिम, 1986](#), [MSME](#), [केंद्रीय बजट 2025-26](#), [भारतीय वन अधनियिम, 1927](#), [चालान परबंधन प्रणाली \(IMS\)](#), [GST](#), [वैकल्पिक वविद समाधान \(ADR\)](#), [73वाँ/74वाँ संशोधन](#), [PARIVESH](#), [MCA21](#) ..

मेन्स के लयि:

नयामक नकिया और जन वश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधनियिम 2023, भारत में वश्वास-आधारति वनियिमन की आवश्यकता ।

[स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया](#)

चर्चा में क्यो?

[जन वश्वास \(प्रावधानों का संशोधन\) अधनियिम 2023](#), जो अगस्त 2023 से प्रभावी है, मामूली उल्लंघनों के लयि **आपराधिक दंडों** को आर्थिक जुर्मानों से प्रतस्थापति करता है। यह अधनियिम **42 केंद्रीय कानूनों के 183 प्रावधानों का अपराधमुक्तकिरण** करता है, जसिका उद्देश्य है- **जीवनयापन की सुगमता, व्यवसाय करने में सुविधा और वश्वास-आधारति नयामक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना** ।

जन वश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधनियिम, 2023 क्या है?

- **परचिय:** यह एक महत्त्वपूर्ण वधियायी सुधार है, जसिका उद्देश्य भारत में व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाना और वश्वास-आधारति वनियिमन को प्रोत्साहति करना है। यह अधनियिम पर्यावरण, कृषि, कॉरपोरेट मामलों सहति 19 मंत्रालयों से संबंधति कानूनों को शामिल करता है।
 - उदाहरण के लयि, [पर्यावरण संरक्षण अधनियिम, 1986](#) के अंतरगत होने वाली प्रक्रयात्मक त्रुटियाँ (procedural lapses) के लयि अब कारावास के स्थान पर **आर्थिक दंड** का प्रावधान है।
- **उद्देश्य:** यह सुधार दंडात्मक व्यवस्था से सुधारात्मक कानूनी तंत्र की ओर एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है, जसिमें छोटे और दुर्भावनाहीन उल्लंघनों के लयि कारावास की सजा के स्थान पर **आर्थिक दंड** का प्रावधान कया गया है, जसिसे भय तथा उत्पीडन कम हो जाता है तथा वशिष रूप से **सुकषम, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs)** के लयि अनुपालन सुगम बनता है।
- **आवश्यकता:** कई पुराने प्रावधानों ने कानूनी अनश्चितता उत्पन्न कर दी है, जसिसे हाशयि पर रह रहे समुदायों पर प्रतकिल प्रभाव पड़ा है और व्यवसायों पर अभयोजन का भय बढ़ गया है।
 - एक समान अनुपालन ढाँचे ने MSME पर असमान दबाव डाला, जसिसे उच्च लागत के कारण औपचारिकीकरण और वसितार में बाधा उत्पन्न हुई।
 - आर्थिक क्षमता को पूरी तरह से वकिसति करने के लयि भारत को **औपनवशिक युग की भय आधारति कानून व्यवस्था** को बदलकर एक **वश्वास-आधारति शासन मॉडल** की आवश्यकता थी, जो मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी में डाल देता था।
- **आगामी कदम:** [केंद्रीय बजट 2025-26](#) में जन वश्वास वधियक 2.0 का प्रस्ताव रखा गया, जसिका उद्देश्य 100 से अधिक प्रावधानों का अपराधमुक्तकिरण करना है तथा वश्वास-आधारति नयामक प्रणाली को और अधिक दृढ़ बनाना है।
- इसमें राज्यों और नगर पालिकाओं से, जहाँ अधिकांश कारावास संबंधी कानून मौजूद हैं, सुधारों को अपनाने, कानूनी ढाँचे को आधुनिक बनाने तथा कारावास के लयि स्पष्ट मानदंड नरिधारति करने का आग्रह कया गया है।

वश्वास-आधारति वनियामक दृष्टिकोण क्या है?

- **परचिय:** यह एक शासन प्रणाली (governance approach) है जसिमें सरकार यह मानती है कवियकत और व्यवसाय सद्भावना (good faith) के साथ कार्य करेंगे तथा कानून का पालन करेंगे, न कउन्हें शुरु से ही संभावति अपराधी मानकर व्यवहार कया जाए।
- **दृष्टिकोण:** यह मॉडल अनावश्यक कानूनी बोझ को कम करने और **स्वैच्छिक अनुपालन (voluntary compliance)** को बढ़ावा देने पर केंद्रति है, जबकि गंभीर उल्लंघनों के लयि कठोर दंड बनाए रखता है।
 - यह **पुलसिगि माइंडसेट** (मामूली उल्लंघनों के लयि कठोर दंड) से **साझेदारी मॉडल** (चूक के लयि उचित परिणामों के साथ स्वैच्छिक

अनुपालन को प्रोत्साहित करना) की ओर स्थानांतरित हो रहा है।

■ प्रमुख विशेषताएँ:

- छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण: प्रक्रियागत या तकनीकी उल्लंघनों के लिये कारावास की सज़ा के स्थान पर जुर्माने का प्रावधान।
- जोखिम-आधारित प्रवर्तन: केवल गंभीर उल्लंघनों (जैसे- धोखाधड़ी, सुरक्षा जोखिम) के लिये सख्त कार्रवाई।
- सरलीकृत अनुपालन: व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिये नौकरशाही लालफीताशाही को कम करना।
- स्व-घोषणा और पारदर्शिता: व्यवसायों/नागरिकों पर केवल उच्च जोखिम वाले मामलों हेतु ऑडिट का अनुपालन करने का विश्वास करना।
- सरकारी हस्तक्षेप में कमी: अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और वसूली को न्यूनतम करना।

भारत को विश्वास-आधारित नियामक दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों है?

- औपनिवेशिक युग के दंडात्मक उपायों को कम करना: भारतीय वन अधिनियम, 1927 जैसे कई औपनिवेशिक काल के कानून नयित्रण के उद्देश्य से बनाए गए थे, न कि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये। ये कानून मामूली उल्लंघनों पर भी आपराधिक दंड आरोपित करते थे, जिससे छोटे व्यवसायों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता था।
 - ये कानून भय, उत्पीड़न और रेंट-सीकंगि (लाभ के लिये दबाव बनाने) का वातावरण बनाते हैं, जिससे विश्वास-आधारित नियामक दृष्टिकोण के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।
- व्यापार सुगमता: अत्यधिक अनुपालन बोझ उद्यमिता में बाधा डालते हैं, जिसमें 75% से अधिक MSME डिजिटल अनुपालन से जूझ रहे हैं तथा 95% को GST के तहत चालान प्रबंधन प्रणाली (IMS) को अपनाने के लिये अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता है।
 - यह अधिनियम वनियमों को सरल, व्यवसायों के लिये अनुपालन को आसान तथा कम चुनौतीपूर्ण बनाकर इस समस्या का समाधान करने में मदद करता है।
- न्यायपालिका पर बोझ कम करना: भारतीय अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से कई सामान्य उल्लंघनों से संबंधित हैं, जिनके लिये आपराधिक मुकदमे के बजाय जुर्माने से बेहतर समाधान किया जा सकता है।
 - मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह जैसे तंत्र मुकदमेबाज़ी को आसान बना सकते हैं तथा अदालतों को अधिक महत्त्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे सकते हैं।
- भ्रष्टाचार और उत्पीड़न में कमी: प्रक्रियागत चूक के लिये कारावास की धमकी से भ्रष्ट अधिकारियों को लाभ कमाने में मदद मिलती है, जबकि अनविर्य सत्यापन, नरीक्षण और अनावश्यक डेटा अनुरोधों से संसाधनों की बर्बादी होती है, विश्वास आधारित प्रणाली में बदलाव से नौकरशाही में कमी आ सकती है साथ ही उत्पादक उपयोग के लिये संसाधनों को मुक्त किया जा सकता है।
- आर्थिक विकास: अनजाने में नयिमों का पालन न करने से आपराधिक आरोपों का डर छोटे व्यवसायों के वसितार में बाधक बनता है, लेकिन मध्य प्रदेश, केरल और हरियाणा जैसे राज्यों ने ऐसे सुधारों को अपनाया है जो क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देते हैं।
 - इस पर नरिमाण करते हुए, जन विश्वास 2.0 (बजट 2025-26) में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण करने, अनुपालन को और आसान बनाने तथा व्यापार-अनुकूल शासन का समर्थन करने की योजना है।
- वकिसति भारत 2047 वज़िन के साथ संतुलन: भारत का अमृत काल वज़िन न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन को बढ़ावा देता है, जिससे नागरिकों और व्यवसायों को न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। एक विश्वास-आधारित प्रणाली परिणाम-आधारित शासन को प्राथमिकता देती है, नवाचार एवं नविश को प्रोत्साहित करती है।

भारत में विश्वास-आधारित वनियमन की दशा में बदलाव में कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

- शासन में औपनिवेशिक अविश्वास की वरिस्त: भारत की औपनिवेशिक वरिस्त में शक और प्रक्रियात्मक नौकरशाही का वर्चस्व रहा है, जिससे अत्यधिक नगिरानी, लालफीताशाही तथा अविश्वास की संस्कृति बनी रहती है। यह प्रणाली नयित्रण पर केंद्रित रहती है, जिससे नयिमों के अनुपालन और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने वाली विश्वास-आधारित वनियमन प्रणाली की ओर स्थानांतरित होना कठिन हो जाता है।
- वनियामक ढाँचा में दोहराव: भारत में कुल 1,536 कानून और 69,233 अनुपालनीय (compliances) हैं, जिनमें से कई या तो अप्रासंगिक हो चुकी हैं या एक-दूसरे के साथ वरिधाभासी हैं। केंद्र सरकार द्वारा जन विश्वास अधिनियम जैसे उपायों से कानूनों का अपराधीकरण कम किया जा रहा है, लेकिन राज्य स्तरीय कठोर वनियम भ्रम उत्पन्न करते हैं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर असमान रूप से भार डालते हैं।
- वकिंदरीकरण और स्वायत्तता का प्रतरोध: 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के बावजूद, स्थानीय सरकारों को वास्तविक स्वायत्तता प्राप्त नहीं है क्योंकि व्यवस्था अब भी ऊपर से नीचे तक नयित्रण आधारित है। अधिकारी जोखिम-आधारित प्रवर्तन के बजाय ऑडिट और दंड को प्राथमिकता देते हैं, जिससे अविश्वास की भावना बनी रहती है।
- विश्वास मेट्रिक्स का अभाव: भारत में विश्वास-आधारित वनियमन की ओर बढ़ते समय एक प्रमुख चुनौती यह है कि विश्वास को वित्तीय या सेवा संकेतकों की भाँति प्रायः मापा नहीं जाता, जिससे नीतियों के प्रभाव का आकलन करना कठिन हो जाता है।
 - इसके अतिरिक्त, ई-बिल प्रणाली और परविश जैसी पहलों के क्रियान्वयन में मौजूद खामियों के कारण देरी होती है, जिससे विश्वास-आधारित शासन ढाँचा बनाने के प्रयास कमज़ोर पड़ते हैं।

भारत में विश्वास-आधारित वनियमन को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है?

- 'एक राष्ट्र, एक व्यवसाय' पहचान प्रणाली: एकीकृत 'एक राष्ट्र, एक व्यवसाय' पहचान प्रणाली को अपनाने से प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकता है, जबकि डिजि लॉकर जैसे उपकरणों का उपयोग करते हुए डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण अपनाने से अनुमोदन में लगने वाले समय में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।
 - डिजि यात्रा और FSSAI के पूर्वानुमेय नियामकीय अद्यतनों जैसी पहलों से प्राप्त शक्तिषाँ वभिन्न कषेत्रों में सुधारों का

मार्गदर्शन करने में सहायक हो सकती हैं।

- कानूनों का सामंजस्यकरण: जन विश्वास 2.0 को 100 से अधिक प्रावधानों के गैर-अपराधीकरण की प्रक्रिया को तेज़ करना चाहिये, विशेषकर राज्य स्तरीय कानूनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जिनमें 80% कारावास संबंधी प्रावधान नहित हैं। ज़रमाने लागू किये जाने चाहिये।
- जोखिम-आधारित प्रवर्तन का संस्थानीकरण: अनुपालन भार का मूल्यांकन करने और दंड को वास्तविक क्षति के अनुरूप बनाने हेतु वनियामक प्रभाव आकलन (RIA) को अनिवार्य किया जाना चाहिये।
 - सामूहिक नरीक्षणों के स्थान पर लक्षित ऑडिट के लिये AI-आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाए और कारावास के लिये स्पष्ट मानदंड निर्धारित किये जाएँ, जिससे इसे केवल गंभीर अपराधों जैसे- धोखाधड़ी या सार्वजनिक सुरक्षा जोखिमों तक सीमित रखा जा सके।
- पारदर्शिता बढ़ाना और विकाधिकार कम करना: MCA21 जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार करते हुए ब्लॉकचेन प्रमाणीकरण को शामिल किया जाए ताकि कागज़ रहित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
 - भ्रष्टाचार के वरिद्ध मुखबरियों की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाए और नरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया में वास्तविक समय की पारदर्शिता हेतु सार्वजनिक डैशबोर्ड का उपयोग किया जाए।
- विश्वास एवं परिणामों का आकलन: सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु अनुपालन सुगमता स्कोर और नागरिक प्रतिक्रिया जैसे मापदंड विकसित किये जाएँ। फनिटेक जैसे क्षेत्रों में पायलट कार्यक्रम प्रारंभ किये जाएँ और नीतियों को परीक्षित करने के लिये नियमित उद्योग-नियामक संवाद हेतु हितधारक परिषदों की स्थापना की जाए।

नषिकरष

जन विश्वास अधिनियम, 2023 छोटे उललंघनों को अपराधमुक्त कर और वनियामक भार को कम कर विश्वास-आधारित शासन की दशिया में एक प्रगतशील परिवर्तन का संकेत देता है। इसके पूर्ण लाभ को प्राप्त करने हेतु भारत को कानूनों को सरल बनाना, स्थानीय नकियाँ को सशक्त करना, डिजिटल उपकरणों को अपनाना और संस्थागत विश्वास का निर्माण करना होगा — जिससे वकिसोनमुखी, नागरिक-केंद्रित तथा कुशल शासन सुनिश्चित हो सके जो वकिसति भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हो।

दृषुट मैन्स प्रश्न:

प्रश्न: "वकिसति समाज की एक प्रमुख वशिषता है सरकार का अपने नागरिकों और संस्थाओं पर विश्वास।" इस संदर्भ में भारत में विश्वास-आधारित शासन की ओर हो रहे परिवर्तन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रलिम्स

प्रश्न. वनिरिमाण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने कौन-सी नई नीतित पहल की है/हैं? (2012)

राष्ट्रीय नविश तथा वनिरिमाण क्षेत्रों की स्थापना

'एकल खडिकी मंजूरी' (सगिल: वडिो क्लीयरेंस) की सुवधि प्रदान करना

प्रौद्योगिकी अधगिरहण तथा विकास कोष की स्थापना

नमिनलखिति कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

???

प्रश्न. "सुधारोत्तर अवधि में सकल-घरेलू-उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पछिडती गई है।" कारण बताइये। औद्योगिक-नीति में हाल में किये गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017)

प्रश्न. राष्ट्रपतिद्वारा हाल में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा माध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किये गए हैं? यह भारत के वविाद समाधान यांत्रिकत्व को कसि सीमा तक सुधारेगा? चर्चा कीजिये। (2015)

